

03/04/2024

## शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. प्रवर्तन निदेशालय (ED) (GS PAPER II: नियामक प्राधिकरण)
2. वर्ल्ड सेंट्रल किचन (डब्ल्यूसीके) (GS PAPER II: एनजीओ)
3. गाजा युद्ध के लिए एक स्मार्ट निकास रणनीति की आवश्यकता है (GS PAPER II: आईआर)
4. एक सुधार विंडो: जीएसटी प्रक्षेपवक्र पर (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था: कराधान)
5. भारत में चुनाव अभियानों में जलवायु संबंधी मुद्दे प्रतिबिंबित होने चाहिए (GS PAPER III: पर्यावरण)
6. लोग फोन पर नियंत्रण खो रहे हैं (GS PAPER III: S&T का उपयोग)

## प्रवर्तन निदेशालय (ED) (GS PAPER II: नियामक प्राधिकरण)

- **भारत की विशेष वित्तीय जांच एजेंसी।** ED भारतीय अर्थव्यवस्था की अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करता है।
- **वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का हिस्सा।** इसे राजस्व विभाग से प्रशासनिक सहायता मिलती है, जबकि नीतिगत मामले आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आते हैं।
- **1956 में** आर्थिक मामलों के विभाग के तहत 'प्रवर्तन इकाई' के रूप में गठित।

### प्राथमिक जिम्मेदारियाँ

1. **मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए):** ED का मुख्य ध्यान मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच और निर्णय लेने पर है। इसमें शामिल है:
  - संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच
  - अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति कुर्क करना
  - अपराधियों पर मुकदमा चलाना
2. **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा):** ED फेमा के नागरिक प्रावधानों को लागू करता है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करना और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। जांच में शामिल हैं:
  - विदेशी मुद्रा नियमों और विनियमों का उल्लंघन
  - हवाला लेनदेन (अवैध धन हस्तांतरण)

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

### वर्ल्ड सेंट्रल किचन (WCK)

- गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) संकट के दौरान भोजन उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है।
- 2010 में स्थापित: प्रसिद्ध शेफ जोस एन्ड्रेस द्वारा।
- मिशन: समुदायों को पोषण देने और संकट के समय और उसके बाद भी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भोजन की शक्ति का उपयोग करना।



## गाजा युद्ध के लिए एक स्मार्ट निकास रणनीति की आवश्यकता है (GS PAPER II: आईआर)

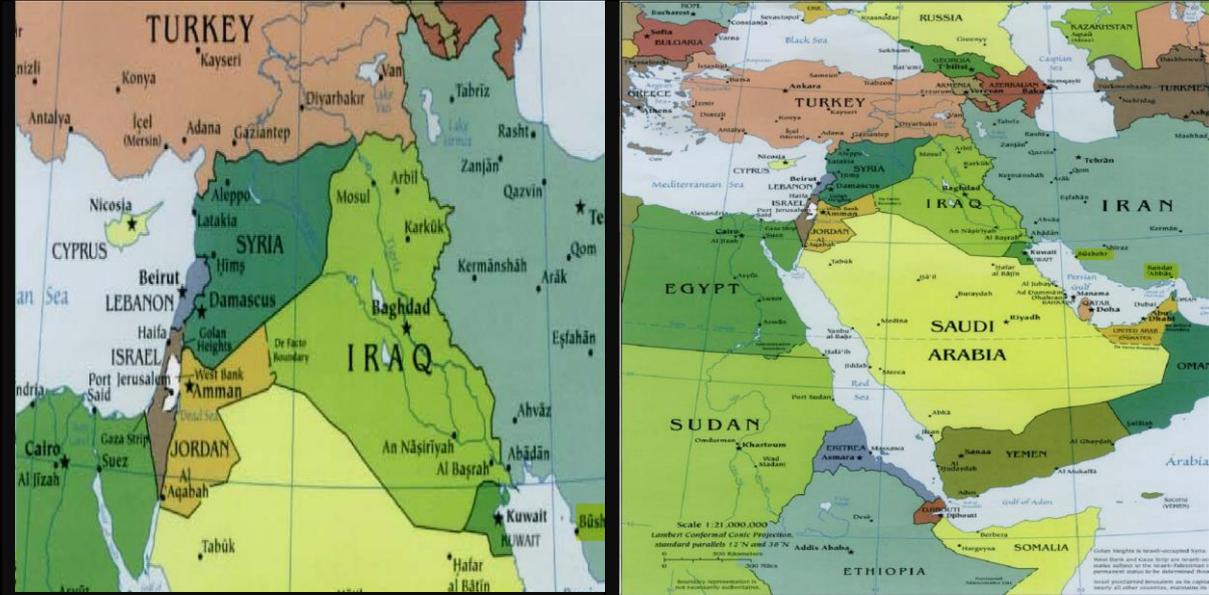
गाजा एक अजेय संघर्ष है और भूगोल और नियति से बंधे इजरायल और फिलिस्तीन को बड़े उतार-चढ़ाव की तलाश करनी होगी

- 25 मार्च, 2024 को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रमज़ान के दौरान गाजा में तत्काल युद्धविराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया।
- पिछले अक्टूबर में दक्षिणी इज़राइल में हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह प्रस्ताव पहला सफल युद्धविराम प्रस्ताव है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूएनएससी में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करने के कारण युद्धविराम प्रस्तावों के पिछले प्रयास विफल हो गए थे। हालाँकि, इस बार, अमेरिका ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिससे प्रस्ताव पारित हो गया।
- इज़राइल ने प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर अपनी नीति छोड़ने और युद्ध के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इज़राइल ने प्रतिक्रिया में वाशिंगटन की एक नियोजित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा रद्द कर दी।
- इज़रायली दबाव के तहत, अमेरिका ने बाद में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी था, जिससे प्रभावी रूप से इज़रायल को युद्धविराम के आह्वान के बावजूद गाजा में अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मिल गई।
- प्रारंभ में युद्धविराम प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, हमास ने बाद में स्थायी युद्धविराम और गाजा से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी की अपनी मांग दोहराई।
- प्रारंभिक आशावाद जल्द ही फीका पड़ गया क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति बरकरार रखी, जिससे यथास्थिति वापस आ गई।

### युद्ध जारी है

- युद्धविराम को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, मिस्र और कतर इस दिशा में काम कर रहे हैं एक को सुविधा प्रदान करना।

- गाजा में अल शिफ़ा अस्पताल पर फिर से हमला करके अपनी कार्रवाई बढ़ा दी , जिससे नागरिक हताहत हुए।
- गाजा के राफा में हवाई हमले और बमबारी हाल ही में तेज हो गई है।
- रिपोर्टों से पता चलता है कि इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान को भी निशाना बनाया , जिसके परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए।
- जवाब में, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल में मिसाइल हमले बढ़ा दिए , जिससे सैन्य संपत्ति को नुकसान हुआ और लोगों की जान चली गई।



- दक्षिण में हौथी लाल सागर में इजरायली, अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को बाधित और अवरुद्ध कर रहे हैं , जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है।
- हाल के अनुमानों के अनुसार, गाजा में युद्ध के कारण 32,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है।
- सीरिया में एक इजरायली हमले ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया , जिसमें 1 अप्रैल को अल कुद्स के एक वरिष्ठ नेता की मौत हो गई, जिससे व्यापक संघर्ष का खतरा बढ़ गया।

## युद्ध के उद्देश्य, उनकी स्थिति

1. इज़राइल ने 7 अक्टूबर को तीन उद्देश्यों के साथ गाजा में जवाबी हमला शुरू किया:

- गाजा को समतल करो.
- हमास को खत्म करो.
- इसके सभी बंधकों को पुनः प्राप्त करें।

2. इज़राइल के उद्देश्यों की समीक्षा:

- गाजा को गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे यह वर्षों तक रहने लायक नहीं रह गया है।
- इज़राइल ने गाजा सीमा पर एक किलोमीटर चौड़ा इलाका समतल कर दिया है।
- अनुमान है कि हमास के केवल 30% लड़ाके ही खत्म किये गये हैं।
- हमास की लड़ने की क्षमता बनी हुई है और उसके रॉकेटों की आपूर्ति कम नहीं हुई है।
- हमास नेता याह्या सिनवार इज़रायली सेना से बच निकला है।

- इज़राइल अपने बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़ाने में विफल रहा है , कुछ की गोलीबारी में मौत की खबर है।
3. हमास के उद्देश्य:
- सामान्यीकरण की बातचीत के बीच दुनिया को फ़िलिस्तीनी राज्य के मुद्दे की याद दिलाएँ इज़राइल और अरब राज्यों के बीच।
  - इज़रायली सेना की कथित अजेयता को उजागर करें इसके समर्थन आधार के लिए.
  - हमास दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा संघर्ष के माध्यम से.
4. युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना चुनौतीपूर्ण है:
- युद्धविराम अक्सर गतिरोध या अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण होता है सैन्य या राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के बजाय।
  - उदाहरणों में अफगानिस्तान और इराक में लंबे समय तक चले अमेरिकी युद्ध शामिल हैं, और चल रहा रूस-यूक्रेन संघर्ष।
  - स्पष्ट रूप से परिभाषित निकास रणनीतियों का अभाव शुरुआती सैन्य जीत के बावजूद संघर्ष लंबा खिंच सकता है।

## इज़राइल पर प्रभाव

- गाजा में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण इज़राइल को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
- इज़रायली सेना को नुकसान और चोटें झेलनी पड़ी हैं
- अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़ रही है, अनुमान है कि लगभग 20% की गिरावट होगी
- प्रधान मंत्री नेतन्याहू को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है
- इज़राइल के सहयोगी अमेरिका ने संकेत दिया है कि इज़राइल को गाजा में अपनी कार्रवाई में संयम दिखाने की जरूरत है.
- इज़राइल को स्पष्ट और प्राप्य अंतिम स्थिति के लिए अपनी युद्ध रणनीति और उद्देश्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि गाजा को सैन्य रूप से हरा दिया गया है, लेकिन हमास का पूरी तरह सफाया होने की संभावना नहीं है।
- इज़राइल के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प शीघ्र युद्धविराम करना हो सकता है गाजा के साथ संघर्ष में.
- इज़राइल गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस ले सकता है और हाल ही में समतल की गई एक किलोमीटर की पट्टी का उपयोग करके गाजा सीमा पर एक निगरानी सह बफर जोन स्थापित कर सकता है।
- निरंतर निगरानी में रहने वाला यह बफर जोन 7 अक्टूबर को हुई घटना जैसी किसी अन्य घटना को रोकने में मदद कर सकता है।
- बंधकों के संबंध में, इज़रायल द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम और बफर जोन पर सहमति जताने के बाद हमास आदान-प्रदान के लिए सहमत हो सकता है।

- भविष्य और संभावित दो-राज्य समाधान को देखते हुए , इसमें शामिल सभी पक्षों को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने और समयबद्ध और स्वीकार्य समाधान पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी।
- इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों एक भौगोलिक और नियति संबंध साझा करते हैं, और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण समझौते की आवश्यकता होगी।
- यदि सहमति हो जाती है, तो इन उपायों से गाजा में वर्तमान अजेय युद्ध से चेहरा बचाने और स्मार्ट तरीके से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है।

## एक सुधार विंडो: जीएसटी प्रक्षेपवक्र पर (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था: कराधान Taxation)

जबरदस्त जीएसटी राजस्व इसके ओवरहाल को प्राथमिकता देने का मौका बनाता है

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह मार्च के मध्य तक 19.9% बढ़ गया, जो संशोधित बजट लक्ष्य का 97% तक पहुंच गया।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ₹20.18 लाख करोड़ रहा , मार्च में सकल जीएसटी राजस्व ₹1.78 लाख करोड़ से अधिक रहा।
- साढ़े छह साल पहले कर लागू होने के बाद से मार्च का जीएसटी संग्रह दूसरा सबसे बड़ा था , जिसे अप्रैल 2023 तक ही पार किया जा सका।
- 2023-24 के लिए औसत मासिक जीएसटी संग्रह 11.6% बढ़कर ₹1.68 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो एक नए राजस्व मानदंड का संकेत देता है।
- 2023-24 के लिए केंद्रीय जीएसटी संग्रह संशोधित अनुमान से अधिक हो गया, जिससे 2024-25 के लक्ष्यों में संशोधन की आवश्यकता हुई।
- बढ़ा हुआ संग्रह आंशिक रूप से पिछली कर मांगों और नकली चालान जैसे उपायों के माध्यम से चोरी को रोकने के प्रयासों का परिणाम हो सकता है।
- शुद्ध जीएसटी राजस्व और घरेलू लेनदेन संग्रह में वृद्धि 2023-24 की अंतिम तिमाही में व्यस्त आर्थिक गतिविधि का संकेत देती है।
- मार्च में माल आयात पर जीएसटी में मामूली गिरावट विवेकाधीन खर्च में कमी का संकेत दे सकती है।
- कुल मिलाकर, जीएसटी प्रक्षेपवक्र सरकार को कर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का विश्वास प्रदान करता है, जिसमें कई कर दरों को तर्कसंगत बनाना और आवश्यक उत्पादों पर शुल्क कम करना शामिल है।
- महामारी-युग के उधारों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जीएसटी मुआवजा उपकरण , संभावित रूप से मार्च 2026 की मौजूदा समय सीमा से पहले समाप्त किया जा सकता है।
- हालाँकि, भारत के हरित लक्ष्यों और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होने से बचने के लिए, किसी भी नए शुल्क को वास्तव में हानिकारक वस्तुओं, जैसे तंबाकू तक सीमित किया जाना चाहिए।

## एक नया निचला स्तर: इज़राइल के गाजा युद्ध और अमेरिकी प्रतिक्रिया पर

## अमेरिका गाजा में इजराइल के अत्याचारों का समर्थक बनता जा रहा है

- ऐतिहासिक रूप से, अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के प्रति सहिष्णु रहा है और उसके परमाणु हथियारों के कब्जे को नज़रअंदाज़ करता है।
- अमेरिका अक्सर इजरायल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों को नज़रअंदाज़ कर देता है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराता है।
- हालाँकि, गाजा में हालिया युद्ध के दौरान इजराइल के प्रति राष्ट्रपति जो बिडेन के दृष्टिकोण की आलोचना हुई है।
- संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए बिडेन प्रशासन को पांच महीने तक संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हजारों फिलिस्तीनी मौतें और विस्थापन हुआ।
- **मतदान से अनुपस्थित रहने के बावजूद, अमेरिका ने प्रस्ताव को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।**
- पूरे युद्ध के दौरान, आगे बढ़ने की चिंताओं के बीच भी, **बिडेन प्रशासन ने इजराइल को सैन्य बिक्री को मंजूरी देना जारी रखा।**
- पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजराइल पर उसके निर्णयों को प्रभावित करने के लिए दबाव डाला, जैसे सहायता में कटौती की धमकी देना या सैन्य बिक्री रोकना।
- अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद, बिडेन का प्रशासन गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों का समर्थन करना जारी रखता है, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन और अकाल के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय संकट की चेतावनी दी है, जिसमें व्यापक भूखमरी और जारी हिंसा के कारण लोग हताहत हो रहे हैं।
- बिडेन से एक राजनेता के रूप में कार्य करने का आह्वान किया गया है, तत्काल युद्धविराम करने, गाजा को सहायता बढ़ाने और संघर्ष जारी रहने पर इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आग्रह किया गया है।

## भारत में चुनाव अभियानों में जलवायु संबंधी मुद्दे प्रतिबिंबित होने चाहिए (GS PAPER III: पर्यावरण)

राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि भारत में चुनावों में जलवायु न्याय के लिए गति उत्पन्न करने की क्षमता है

**प्रश्न: भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मजबूत किया जा सकता है? प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करें। (200 शब्द/12.5 अंक)**

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट बताती है कि 2023 विश्व स्तर पर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था।

- औसत तापमान वृद्धि 1.45 डिग्री सेल्सियस है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सहमत सीमा के करीब है।
- तापमान में यह वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, चिंता का कारण है।
- समुद्र के तापमान, ग्लेशियर के पीछे हटने और अंटार्कटिक बर्फ के आवरण में कमी सहित विभिन्न जलवायु संकेतकों के रिकॉर्ड टूटते हुए देखे गए।
- विश्व स्तर पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और लू, भारी वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं।
- इन चरम मौसम की घटनाओं ने कृषि सहित विभिन्न गतिविधियों को बाधित कर दिया है और दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं।
- रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई प्रतिक्रियाओं के समान सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

## प्रगति और शमनकारी कदम

- 18वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक प्रगति ने जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- मशीनीकरण और तकनीकी नवाचार इस प्रगति के प्राथमिक चालक रहे हैं।
- हालाँकि, इस प्रगति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ गया है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हुआ है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान दे रहा है।
- 4 नवंबर, 2016 को लागू हुए पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
- ने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए कदम उठाए हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहल हैं जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए।
- इन प्रयासों के बावजूद, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की नवीनतम रिपोर्ट वैश्विक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।

## अवसर के रूप में चुनाव का मौसम

- भारत में चुनावी मौसम उत्सव, जोशीली बहस और बदलाव की उम्मीद लेकर आता है।
- चुनावी मौसम के साथ मेल खाने वाली वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर चर्चा को प्रेरित करती है।
- रिपोर्ट को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए।
- पार्टियों को जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- राजनीतिक मतभेद मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना व्यापक सार्वजनिक हित में है।
- पार्टियों को भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन कार्यों पर भारत का नेतृत्व उसकी वैश्विक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है।

- आर्थिक समृद्धि और लोगों की भलाई के एजेंडे का अभिन्न अंग होना चाहिए।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER III: जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग

प्रश्न: ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की स्थिति चुनावी मौसम के साथ मेल खाती है, भारत में जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और जलवायु न्याय को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों और सक्रिय नागरिकों की भूमिका का विश्लेषण करें। (150 शब्द/10 अंक)

### उत्तर दृष्टिकोण

- वैश्विक जलवायु रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए प्रमुख बिंदुओं के साथ उत्तर का परिचय दें।
- जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं के बारे में विस्तार से बताएं।
- फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और जलवायु न्याय को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों और सक्रिय नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डालें।
- एक भविष्योन्मुखी टिप्पणी के साथ समापन करें।

### उत्तर

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन की चिंताजनक वास्तविकता पर प्रकाश डाला है। इससे पता चला कि 2023 विश्व स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था और इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। जैसा कि भारत चुनावों के लिए तैयार है, यह राजनीतिक दलों के लिए जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और देश में जलवायु न्याय को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

#### वैश्विक जलवायु स्थिति से जुड़ी चिंताएँ

- रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है, जिसमें विभिन्न जलवायु संकेतक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिनमें समुद्र का तापमान, ग्लेशियर का पीछे हटना और अंटार्कटिक के बर्फ के आवरण का कम होना शामिल है।
- लू, भारी वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं।
- इस संदर्भ में, राजनीतिक दलों को अपने चुनाव अभियानों में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने के महत्व को समझना चाहिए।
- पेरिस समझौता, एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, जिसने दुनिया भर के देशों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हालांकि, समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, WMO की नवीनतम रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।

#### राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका

- इस पृष्ठभूमि में, चुनावी मौसम राजनीतिक दलों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर जनता के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- पार्टियों को जलवायु परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ठोस कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हालांकि राजनीतिक मतभेद मौजूद हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना व्यापक सार्वजनिक हित में है और इसे सभी दलों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- इसके अलावा, जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति देश की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक दलों को भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए।
- इन उपायों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लागू करना और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल हो सकता है।

- **सार्वजनिक जवाबदेही:** नागरिकों के लिए यह मांग करना अनिवार्य है कि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को शामिल करें।
- जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करके, व्यक्ति जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए पार्टियों पर दबाव डाल सकते हैं।
- मतदाताओं को जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर पार्टी के एजेंडे का मूल्यांकन करना चाहिए।
- **जमीनी स्तर पर आंदोलन:** जमीनी स्तर के आंदोलन और पर्यावरण वकालत समूह जलवायु कार्रवाई के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- रैलियाँ, विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियान आयोजित करके, ये समूह राजनीतिक चर्चा को प्रभावित कर सकते हैं और पार्टियों को जलवायु मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- **पारदर्शिता और निगरानी:** नागरिकों को राजनीतिक दलों से उनकी जलवायु नीतियों और पहलों के संबंध में पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए।
- पार्टियों को अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं की प्रगति पर नियमित अपडेट प्रदान करना चाहिए और सार्वजनिक और नागरिक समाज संगठनों से जांच के लिए खुला रहना चाहिए।

इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन कार्यों पर भारत का नेतृत्व और सक्रिय नागरिकता इसकी वैश्विक स्थिति के लिए आवश्यक है, और राजनीतिक दलों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करके, पार्टियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि जलवायु न्याय देश की भविष्य की समृद्धि और भलाई के लिए प्राथमिकता बनी रहे।

## लोग फोन पर नियंत्रण खो रहे हैं (GS PAPER III: S&T का उपयोग)

इंटरनेट सेवाओं तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ताओं को ऐप्स वह तरीका नहीं चुनना चाहिए जो उन्हें चुनना चाहिए। “इमर्सिव” अनुभव पहले उपयोगकर्ताओं को डुबो रहा था और अब व्यवसायों को डुबो रहा है

- इंटरनेट को व्यक्तिगत मशीनों को केंद्रीय नियंत्रण के बिना एक-दूसरे से जुड़ने और संचार करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- प्रत्येक कनेक्टेड मशीन में यह निर्णय लेने की शक्ति थी कि वांछित सेवाओं के लिए किससे संवाद किया जाए।
- नेटवर्क परत में न्यूनतम द्वारपाल थे, मुख्य रूप से आईपी पते आवंटित करने और .com और .org जैसे डोमेन नामों के लिए रूट सर्वर प्रबंधित करने जैसे कार्यों के लिए।
- इस विकेन्द्रीकृत डिज़ाइन के कारण 1990 और 2000 के दशक में इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ।
- **ईमेल, वेबसाइट और चैट** जैसी विभिन्न सेवाएँ सामने आईं, जिससे सूचना साझा करना और ई-कॉमर्स संभव हो गया।
- मानकीकृत प्रोटोकॉल और भाषाओं की बदौलत वेब ब्राउज़र के साथ वेबसाइटों तक पहुंच आसान हो गई है।
- प्रारंभ में, **याहू ने विषय के आधार पर वर्गीकृत वेबसाइटों की एक निर्देशिका प्रदान की।**
- वेबसाइटों में वृद्धि के साथ, **Google ने उपयोगकर्ता प्रश्नों के आधार पर प्रासंगिक वेब पेजों को तुरंत ढूँढने के लिए एक खोज इंजन पेश किया।**

## नियंत्रण सौंपना

- आईफोन जैसे मोबाइल उपकरणों के आगमन के साथ, वेबसाइटें छोटी स्क्रीन पर देखने के लिए अनुकूलित होने लगीं।
- Apple ने डेवलपर्स को मोबाइल उपकरणों पर अपने Safari ब्राउज़र के लिए वेब एप्लिकेशन (ऐप) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- डेवलपर्स इन उपकरणों के लिए अधिक नियंत्रण और देशी ऐप्स बनाने की क्षमता चाहते थे, जिसके कारण ऐपल ने 2008 में तीसरे पक्ष के देशी कोड के लिए ऐप स्टोर खोला।
- ऐप्स ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो सीधे मोबाइल फोन पर चलते हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है क्योंकि वे कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और उपकरणों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं।
- Google की सुरक्षा टीम ने इन जोखिमों को कम करने के लिए 2009 में नेटिव क्लाइंट नामक एक सैंडबॉक्स विकसित किया, लेकिन व्यापक रूप से इसे अपनाया नहीं गया और ऐप स्टोर हमेशा की तरह ऐप्स को अनुमति देते रहे।
- वेब मानक जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट-साइड कंप्यूटिंग के लिए एक सुरक्षित भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए विकसित हुए, जो ब्राउज़रों द्वारा समर्थित है, अविश्वसनीय सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक सुरक्षित सैंडबॉक्स प्रदान करता है।
- समय के साथ जावास्क्रिप्ट परिपक्व हुई, उपयोगकर्ताओं की मशीनों पर अविश्वसनीय कोड चलाने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान किया गया, कम जोखिम के साथ अविश्वसनीय वेबसाइटों को ब्राउज़ करने में सक्षम बनाया गया।
- व्यवसायों ने ऐप्स को प्राथमिकता दी क्योंकि वे बिना किसी प्रतिबंध के लाखों उपकरणों पर मूल कोड चला सकते थे।
- उपयोगकर्ताओं को अधिक गहन अनुभव के लिए ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन इसके लिए एसएमएस, फ़ोटो, वीडियो और स्थान पर नियंत्रण छोड़ना और विज्ञापन अवरोधन जैसी ब्राउज़र सुविधाओं को खोना आवश्यक था।
- ऐप स्टोर ने द्वारपाल के रूप में कार्य करते हुए उपयोगकर्ताओं को ऐप सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन मैलवेयर, धोखाधड़ी और डेटा चोरी की घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दीं।
- डेवलपर्स सुरक्षित के रूप में लेबल करके ऐप स्टोर पर ऐप्स प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे बेईमान ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं का शोषण करने की घटनाएं सामने आ सकती हैं।
- एक दशक पहले उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, उपयोगकर्ताओं और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के कारण ऐप्स की लोकप्रियता बनी रही, ऐप स्टोर्स को 15% से 30% तक के ऐप टैक्स से लाभ हुआ।
- व्यवसाय, जो शुरू में उपयोगकर्ता नियंत्रण के लिए ऐप्स की ओर आकर्षित हुए थे, अब राजस्व बंटवारे का विरोध करते हैं, जिससे Google जैसी कंपनियों के खिलाफ अविश्वास के मामले सामने आ रहे हैं।
- एपिक गेम्स ने ऐपल के खिलाफ मुकदमा जीता, लेकिन ऐप स्टोर से हटाने जैसे नतीजों का सामना करना पड़ा, जबकि Google को अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा, लेकिन यूजर चॉइस बिलिंग जैसे वैकल्पिक बिलिंग तरीकों की शुरुआत की।

## एक भीषण लड़ाई

- संघर्ष जारी है, ऐप स्टोर ऐप टैक्स से उत्पन्न राजस्व को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं।

- व्यवसाय बिना किसी ऐप टैक्स के ऐप स्टोर की वकालत कर रहे हैं या यहां तक कि भारतीय ऐप स्टोर जैसे राष्ट्रीय ऐप स्टोर की स्थापना का प्रस्ताव भी दे रहे हैं।
- ऐप स्टोर, व्यवसायों और अदालतों से जुड़ी इस लड़ाई के परिणाम के बावजूद, उपयोगकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि ऐप्स के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच आदर्श विकल्प नहीं हो सकता है।
- आकर्षण उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए हानिकारक साबित हुआ है, जिसका नियंत्रण अंततः ऐप्पल और Google जैसे ऐप स्टोर दिग्गजों के हाथों में है।

### प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानी पर विचार करें:

1. लेबनान - बेरूत
2. सीरिया - काहिरा
3. जॉर्डन - दमिश्क
4. मिस्र - अम्मान

उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं/हैं?

- a. केवल एक
- b. सिर्फ दो
- c. केवल तीन
- d. चारों

प्रश्न 2: इराक की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है?

- a. नील नदी
- b. टाइग्रिस नदी
- c. फ़रात नदी
- d. जॉर्डन नदी

प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का मुख्य उद्देश्य नहीं है?

- a. न लागत में वृद्धि
- b. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनानाकरों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना
- c. एक सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार को बढ़ावा देना
- d. व्यवसायों के लिए अनुपाल

प्रश्न 4: जीएसटी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है:

- a. सीधा कर
- b. अप्रत्यक्ष कर
- c. निगमित कर
- d. धन कर

प्रश्न 5: जीएसटी व्यवस्था के तहत, निम्नलिखित में से किस कर को जीएसटी में शामिल किया गया है?

- a. मूल्य वर्धित कर (वैट)
- b. आयकर
- c. संपत्ति कर
- d. सीमा शुल्क

प्रश्न 6: वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर किस प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है?

1. आईजीएसटी
2. सीजीएसटी
3. यूटीजीएसटी
4. एसजीएसटी

उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं/हैं?

- a. केवल एक
- b. सिर्फ दो
- c. केवल तीन
- d. चारों

प्रश्न 7: निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. यूके
2. जर्मनी
3. जापान
4. रूस

उपरोक्त में से कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं/हैं?

- a. केवल एक
- b. सिर्फ दो
- c. केवल तीन
- d. चारों

प्रश्न 8: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ठोस प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है?

- a. 15 में से 5
- b. 15 में से 7
- c. 15 में से 9
- d. 15 में से 11

प्रश्न 9: उपकर और अधिभार के बीच मुख्य अंतर को पहचानें।

- a. केंद्र सरकार द्वारा उपकर एकत्र किया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिभार एकत्र किया जाता है।
- b. उपकर स्थायी होता है, जबकि अधिभार अस्थायी होता है।
- c. उपकर का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जबकि अधिभार सामान्य राजस्व में जोड़ा जाता है।
- d. उपकर सभी करदाताओं पर लागू होता है, जबकि अधिभार केवल उच्च आय वालों पर लागू होता है।

प्रश्न 10: उपकर और अधिभार किस निधि में एकत्रित किये जाते हैं?

- a. भारत की संचित निधि
- b. भारत की आकस्मिकता निधि
- c. भारत का सार्वजनिक खाता
- d. राष्ट्रीय निवेश कोष

<p>प्रश्न 1: निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानी पर विचार करें:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लेबनान - बेरूत</li> <li>2. सीरिया - काहिरा</li> <li>3. जॉर्डन - दमिश्क</li> <li>4. मिस्र - अम्मान</li> </ol> <p>उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं/हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. केवल एक</li> <li>b. सिर्फ दो</li> <li>c. केवल तीन</li> <li>d. चारों</li> </ol>	<p>उत्तर: (ए)</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>लेबनान की राजधानी बेरूत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मिस्र की राजधानी काहिरा है।</p>
<p>प्रश्न 2: इराक की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. नील नदी</li> <li>b. टाइग्रिस नदी</li> <li>c. फ़रात नदी</li> <li>d. जॉर्डन नदी</li> </ol>	<p>उत्तर: (बी)</p> <p>स्पष्टीकरण: जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन नदी के तट पर स्थित है, जो मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषता है। टाइग्रिस नदी पर बगदाद।</p>
<p>प्रश्न 3: उस देश की पहचान करें जिसकी राजधानी उसका सबसे बड़ा शहर भी है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. लेबनान</li> <li>b. सीरिया</li> <li>c. जॉर्डन</li> <li>d. मिस्र</li> </ol>	<p>उत्तर: (ए) लेबनान</p> <p>स्पष्टीकरण: बेरूत लेबनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर दोनों है। हालाँकि दमिश्क, अम्मान और काहिरा बड़े शहर हैं, लेकिन वे अपने देशों में सबसे बड़े शहर नहीं हैं।</p>
<p>प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का मुख्य उद्देश्य नहीं है?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना</li> <li>b. एक सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार को बढ़ावा देना</li> <li>c. व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत में वृद्धि</li> <li>d. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना</li> </ol>	<p>उत्तर: (सी)</p> <p>स्पष्टीकरण: जीएसटी का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत को कम करने सहित जटिलताओं को कम करना है।</p>
<p>प्रश्न 5: जीएसटी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. सीधा कर</li> <li>b. अप्रत्यक्ष कर</li> <li>c. निगमित कर</li> <li>d. धन कर</li> </ol>	<p>उत्तर: (बी) अप्रत्यक्ष कर</p> <p>स्पष्टीकरण: जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है, जिससे यह एक अप्रत्यक्ष कर बन जाता है (आय अर्जक द्वारा सरकार को सीधे भुगतान नहीं किया जाता है)।</p>
<p>प्रश्न 6: जीएसटी व्यवस्था के तहत, निम्नलिखित में से किस कर को जीएसटी में शामिल किया गया है?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. मूल्य वर्धित कर (वैट)</li> <li>b. आयकर</li> </ol>	<p>उत्तर: (ए) मूल्य वर्धित कर (वैट)</p> <p>स्पष्टीकरण: जीएसटी ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया, जिनमें वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और बहुत कुछ शामिल हैं।</p>

<p>c. संपत्ति कर d. सीमा शुल्क</p>	
<p>प्रश्न 7: वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर किस प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है?</p> <p>a. आईजीएसटी b. सीजीएसटी और एसजीएसटी c. यूटीजीएसटी d. इनमें से कोई भी नहीं</p>	<p>उत्तर: (बी) सीजीएसटी और एसजीएसटी</p> <p>स्पष्टीकरण: अंतर-राज्य लेनदेन (एक राज्य के भीतर) पर केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दोनों लगते हैं।</p>
<p>प्रश्न 8: निम्नलिखित देशों पर विचार करें:</p> <p>a. यूके b. जर्मनी c. जापान d. रूस</p> <p>उपरोक्त में से कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं/हैं?</p> <p>1. केवल एक 2. सिर्फ दो 3. केवल तीन 4. चारों</p>	<p>उत्तर: (बी) रूस</p> <p>स्पष्टीकरण: UNSC के पांच स्थायी सदस्य हैं (P5): चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।</p>
<p>प्रश्न 9: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ठोस प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है?</p> <p>a. 15 में से 5 b. 15 में से 7 c. 15 में से 9 d. 15 में से 11</p>	<p>उत्तर: (सी)</p> <p>स्पष्टीकरण: किसी ठोस प्रस्ताव को पारित करने के लिए नौ सकारात्मक वोटों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कोई भी स्थायी सदस्य (P5) अपनी वीटो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है।</p> <p>अनुच्छेद 27: सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा किए जाएंगे।</p>
<p>प्रश्न 10: यूएनएससी संकल्प निम्नलिखित में से किस कार्रवाई को अधिकृत कर सकता है?</p> <p>a. आर्थिक प्रतिबंध लगाना b. शांति सेना की तैनाती c. अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की स्थापना d. ऊपर के सभी</p>	<p>उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी</p> <p>स्पष्टीकरण: यूएनएससी के प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं और शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए कई प्रकार की कार्रवाइयों को अधिकृत कर सकते हैं।</p>
<p>प्रश्न 11: यूएनएससी के उस प्रस्ताव की पहचान करें जिसने 1990 में कुवैत पर इराकी आक्रमण का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।</p> <p>a. संकल्प 660 b. संकल्प 1244</p>	<p>उत्तर: (ए) संकल्प 660</p> <p>स्पष्टीकरण: संकल्प 660 ने कुवैत पर इराकी आक्रमण की निंदा की और इराकी बलों की तत्काल</p>

<p>c. संकल्प 1373 d. संकल्प 242</p>	<p>वापसी की मांग की। यह संघर्ष की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक समाधान था</p>
<p>प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिभार का उदाहरण है?</p> <p>a. सड़क और बुनियादी ढांचा उपकरण b. स्वच्छ भारत उपकरण c. कृषि कल्याण उपकरण d. आयकर अधिभार</p>	<p>उत्तर: (डी) आयकर अधिभार</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>अधिभार मौजूदा कर राशि पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर है। भारत में, उच्च कर योग्य आय वाले व्यक्तियों या निगमों पर आयकर अधिभार लागू किया जाता है।</p>
<p>प्रश्न 13: उपकरण और अधिभार के बीच मुख्य अंतर को पहचानें।</p> <p>a. केंद्र सरकार द्वारा उपकरण एकत्र किया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिभार एकत्र किया जाता है। b. उपकरण स्थायी होता है, जबकि अधिभार अस्थायी होता है। c. उपकरण का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जबकि अधिभार सामान्य राजस्व में जोड़ा जाता है। d. उपकरण सभी करदाताओं पर लागू होता है, जबकि अधिभार केवल उच्च आय वालों पर लागू होता है।</p>	<p>उत्तर: (सी) उपकरण का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जबकि अधिभार सामान्य राजस्व में जोड़ा जाता है।</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>मुख्य अंतर धन के उपयोग में है। उपकरण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि अधिभार सरकार के सामान्य राजस्व पूल में जुड़ जाता है।</p>
<p>प्रश्न 14: उपकरण और अधिभार किस निधि में एकत्रित किये जाते हैं?</p> <p>a. भारत की संचित निधि b. भारत की आकस्मिकता निधि c. भारत का सार्वजनिक खाता d. राष्ट्रीय निवेश कोष</p>	<p>उत्तर: (ए) भारत की समेकित निधि</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकरण और अधिभार दोनों भारत के समेकित कोष का हिस्सा बनते हैं।</p>